यह है वास्तविक अर्थव्यवस्था

साभार: द हिंदू
(21 नवंबर, 2017)

पूजा मेहरा
(पत्रकार)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-III (भारतीय अर्थव्यवस्था) से संबंधित है।

भारत को औद्योगिक विकास की गति को सुधारने के लिए सुधारात्मक कदमों की आवश्यकता है।

वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में अच्छी खबरें सुनने को मिल रही है, मूडीज से रेटिंग का उन्नयन और इससे पहले, विश्व बैंक की दिक्कत को लेकर व्यापार सूचकांक में भारत की स्थिति में बढ़ोतरी ने सुर्खियों में वर्चस्व कायम किया है। यह सुधार निवेशकों के लिए भारत के बढ़ते आकर्षण को दर्शाता है और प्रशंसा के योग्य भी है। हालांकि, यह बुनियादी स्तर पर वास्तविकता के साथ सुमेलित नहीं है और न ही इससे अंतरराष्ट्रीय पहचान को नुकसान पहुचने वाला है।

जैसा कि विदेश में देखा गया है

मूडी के रेटिंग्स समय के साथ अपने ऋण की सेवा के लिए सरकार की क्षमताओं के प्रक्षेप पथ के अपने आकलन पर आधारित हैं। भारत के लिए उच्च रेटिंग सरकार के ऋण के लिए कम जोखिम वाले ग्रेड का संकेत देती है और इसे ऊपर उठाने की लागत कम कर सकती है। उन्नयन का महत्व अपने समय पर बिलकुल सही है। 2015 में, मूडीज ने भारत के लिए 'स्थिर' से 'सकारात्मक' दृष्टिकोण को बदल दिया था, जबकि रेटिंग को अपरिवर्तित रखा था। इस दृष्टिकोण का कुछ हफ्तों बाद आने वाली अगली मौद्रिक समीक्षा में रेखा के नीचे बचाव करना मुश्किल हो जायेगा। भारत को 'स्थिर' दृष्टिकोण के स्तर में वापस धकेल दिया जा सकता है।

स्टैंडर्ड एंड पूअर्स जैसे अन्य रेटिंग एजेंसियों द्वारा संशोधनों की संभावना बढ़ गई है, लेकिन उन उन्नयनों को स्वचालित नहीं किया जाएगा। उन्हें बांटने के लिए, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार को अपने राजकोषीय प्रतिरक्षण को संरक्षित करना होगा और राज्यों को लोकलुभावनवाद और दुस्साहस से दूर रखना होगा।

इतना आशावादी नहीं: जहां तक बुनियादी स्तर पर विकास का संबंध है, मौजूदा वित्तीय वर्ष की पहली छमाही में अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन अगले सप्ताह ज्ञात होगा। 30 सितंबर को समाप्त होने वाली दूसरी तिमाही के लिए विकास अनुमान इस महीने के अंत में जारी होगा। निर्यात डेटा और त्वरित अनुमान, अप्रैल से सितंबर के लिए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) से बाहर हैं। अर्थव्यवस्था में गैर-कृषि उत्पादन, निवेश और खपत का सूचक कोई सुंदर तस्वीर पेश नहीं करता।

औद्योगिक उत्पादन के लिए समाचार सही नहीं है। विकास दर 2.5% तक कमजोर हुई है, जो एक साल पहले 5.8% था। विनिर्माण मोर्चे पर, समाचार खराब है, जहाँ विकास दर 1.9% है, जो एक साल पहले 6.1% थी। यहाँ बुनियादी ढांचा और निर्माण की एक ही कहानी है: पिछले वर्ष की पहली छमाही में विकास दर 2% है, जो पिछले साल की पहली छमाही में 4.9% की तुलना में कमजोर है।

उपभोक्ता और निवेशको की भावनाओं को ठेस पंहुचा है। पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में वर्ष के पहले छमाही में पूंजीगत सामान और उपभोक्ता उत्पादन कम था। सुविधा का एकमात्र स्रोत उपभोक्ता गैर-टिकाऊ रहा है, जिसके उत्पादन में वृद्धि 7.4% हो गई, हालांकि यह एक साल पहले 10% से अधिक वृद्धि की तुलना में धीमी गति से था।

इसलिए, आईआईपी इंगित करता है कि औद्योगिक क्षेत्र बेहद अस्थिर जमीन पर है। उत्सव और बाद के फसल के मौसम के खर्च से मांग में वृद्धि की उम्मीद थी, लेकिन सितंबर कमजोर महीने के रूप में रहा। अब आशा है कि अक्टूबर, जिसके लिए अभी तक आंकड़े नहीं हैं, वे बेहतर होगा। यहाँ परिस्थितियां नौकरी सृजन के लिए अनुकूल नहीं दिख हैं। इस साल तक औद्योगिक प्रदर्शन साधारण रही, किन्तु यह 2012-13 की तुलना में कमजोर है, जो कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार के तहत सबसे खराब वर्षीय विकास दर रही थी। उस साल अपने 10-वर्षीय कार्यकाल में वार्षिक आईआईपी विकास 3.3% था। इस वर्ष के पहले छह महीनों में यह 2.5% था। आईआईपी - विनिर्माण, पूंजीगत सामान, उपभोक्ता वस्तुओं और बुनियादी ढांचे और निर्माण के हर एक प्रमुख क्षेत्र में विकास - इस वर्ष अब तक 2012-13 से यह कमजोर है। अगर औद्योगिक विकास गति में हानि की वर्तमान दर पर सुधारात्मक कदम नहीं उठाए जाते हैं, तो इस साल यूपीए सरकार की नीति पक्षाघात के चरण से भी बदतर हो सकता है।

डिजाइन द्वारा आईआईपी कवरेज संगठित क्षेत्र तक सीमित है। असंगठित क्षेत्र में विघटन अलग-अलग मापा जाएगा। सिर्फ अर्थव्यवस्था के समग्र विकास पर औद्योगिक क्षेत्र का कितना ड्रैग देखा जाना चाहिए। अर्थव्यवस्था, कृषि और सेवाओं के अन्य क्षेत्रों में, विशेष रूप से इसे आगे बढ़ाने की उम्मीद है।

निर्यात मोर्चे पर: निर्यात दो अंकों की वृद्धि के साथ सुधार के संकेत दिखा रहा था। अगस्त और सितंबर अच्छे महीनों के रूप में सामने आये थे, लेकिन अक्टूबर में एक छोटी सी गिरावट दर्ज की गई, इसलिए इससे पहले कि निष्कर्ष निकाला जाए, उससे पहले एक अधिक विस्तृत डेटा पॉइंट्स की आवश्यकता होगी। जिससे यह पता चले कि एक स्थायी सुधार पूरी तरह से सफल हो पाया है या नहीं। चमड़े, जवाहरात, आभूषण, हस्तशिल्प, रेडीमेड परिधान और कालीनों के रोजगार-गहन क्षेत्रों में गिरावट तेज है।

वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली की दुर्बलताओं के चलते निर्यातकों ने तरलता में कमी करना शुरू कर दिया है। वे शिकायत करते हैं कि उनके रिफंड दावों को चार महीने से जारी नहीं किया गया है। कार्यशील पूंजी तक सीमित पहुंच वाली छोटी कंपनियों को झटका लगा है।

विकास संकट राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबन्धन सरकार के स्वयं के द्वारा निर्मित है। यदि विमुद्रीकरण से मांग को कमजोर बनया, तो जीएसटी ने आपूर्ति पर विनाशकारी प्रभाव डाला है। इस दोहरे झटके ने उद्योग की समस्याओं को और अधिक गंभीर बना दिया है, जो पहले से ही मंदी के साथ संघर्ष कर रहा था। यह वास्तविक अर्थव्यवस्था है जो सरकार के एजेंडे पर हावी हो रहा है।

संबंधित तथ्य

क्रेडिट रेटिंग

- किसी भी देश, संस्था या व्यक्ति आदि की कर्ज लेने या उसे चुकाने की क्षमता का मूल्यांकन होती है, अर्थात कोई व्यक्ति, संस्था या देश आर्थिक रूप से कितना मजबूत है और कितना कर्ज लेने या उसे चुकाने की क्षमता रखता है।
- क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां किसी देश की साख का मूल्यांकन करते समय उसका आर्थिक विश्लेषण करती हैं और यह पता लगाती हैं कि वह कितना सक्षम है। ये एजेंसियां किसी भी देश की क्रेडिट रेटिंग तय करते समय कोई निश्चित फार्मूला नहीं अपनाती हैं बल्कि अपने अनुभवों और आंकड़ों का इस्तेमाल करती हैं। वे खुद ही किसी देश या संस्था की रेटिंग तय करती हैं।

क्या है मूडीज:

- दुनिया की तीन बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों में से एक मूडीज है। दो अन्य रेटिंग एजेंसियों में फिच और स्टैंडर्ड एंड पूअर्स शामिल हैं। वर्ष 1908 में मूडीज की स्थापना की गई थी।
- यह एजेंसी सरकारों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों द्वारा जारी बांड पर आधारित वित्तीय अनुसंधान करती है। इसी आधार पर वह देश की क्रेडिट रेटिंग जारी करती है।
- कुल मिलाकर उसकी रेटिंग के आधार पर यह तय होता है कि अमुक देश में निवेश कितना सुरक्षित है। मूडीज 'एएए' से लेकर 'सी' तक की रेटिंग जारी करती है। 'एएए' सबसे बेहतर और 'सी' सबसे खराब रेटिंग है।

नोट: अमेरिकी रेटिंग्स एजेंसी मूडीज ने भारत की रेटिंग सुधार कर Baa3 से Baa2 कर दिया है। साथ ही इसने इन्वेस्टर रेटिंग को भी सकारात्मक से स्थिर कर दिया। इससे पहले 13 साल पहले 2004 में मूडीज ने भारत की रेटिंग बढ़ाई थी।

रेटिंग की श्रेणियां:

- एएए: सबसे मजबूत सबसे बेहतर
- एए: वादों को पूरा करने में सक्षम
- ए: वादों को पूरा करने की क्षमता पर विपरीत परिस्थितियों का पड़ सकता है असर
- बीबीबी: वादों को पूरा करने की क्षमता, लेकिन विपरीत परिस्थितियों से आर्थिक स्थितियां प्रभावित होने की संभावना अधिक।
- सीसी: वर्तमान में बहुत कमजोर
- डी: ऋण लौटाने में असफल

क्रेडिट रेटिंग बढ़ाए जाने से लाभ

1. **सस्ता और आसान कर्ज:** देश में भी कर्ज सस्ता होगा। भारतीय कंपनियों को भी सस्ता कर्ज मिलेगा।
2. **विदेशी कंपनियां लगाएंगी भारत में पैसा:** मूडीज की रेटिंग का बांड्स पर असर होगा। दूसरी रेटिंग एजेंसियां भी भारत की रेटिंग बढ़ा सकती हैं। भारत पर विदेशी निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा।
3. **आर्थिक विकास तेज होगा:** रेटिंग में सुधार से लगता है कि नोटबंदी और जीएसटी का असर कम हो चुका है। लोगों का भरोसा बढ़ रहा है, जिससे विकास दर तेज होगी।
4. **महंगाई घटने की उम्मीद:** सुधार पर डटे रहने से विकास दर बढ़ी है। महंगाई का डर कम होता दिख रहा है। आगे महंगाई और कम होने की उम्मीद है।
5. **शेयर बाजार में रिटर्न बढ़ेगा:** शेयर बाजार में उत्साह का माहौल है। शेयर बाजार में नई शुरुआत हो चुकी है। आम लोगों को भी अच्छे रिटर्न मिलेंगे।
6. **रुपया मजबूत होगा:** देश में आर्थिक माहौल बेहतर होने और विदेशी निवेश बढ़ने से रुपया भी मजबूत होगा। इसके अलावा बांड और इक्विटी मार्केट मजबूत होगा। सरकार का भी राजस्व बढ़ेगा।

चिंताएँ-

- मूडीज ने निजी क्षेत्र के निवेश में कमी और GST के सफल क्रियान्वयन की चुनौती को लेकर चिंता व्यक्त की है।
- बैंकों के 'बैड लोन' की समस्या को लेकर भी एजेंसी ने चिंता जाहिर की है।
- एजेंसी ने इस बात के लिये भी सचेत किया है कि कर्ज का बड़ा बोझ भारत की क्रेडिट प्रोफाइल के समक्ष एक गंभीर चुनौती बना हुआ है।
- कुछ अर्थशास्त्रियों के अनुसार क्रेडिट रेटिंग में सुधार से होने वाले लाभ छोटे उद्यमियों की बजाए ज्यादातर बड़ी कंपनियों को प्राप्त होंगे। अतः सरकार की कोशिश होनी चाहिये कि माहौल के सुधरने का लाभ सभी क्षेत्रों को प्राप्त हो।

संभावित प्रश्न

हाल ही में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत की रेटिंग में सुधर किया है, जो पिछले कुछ समय में सरकार द्वारा किए गए आर्थिक और संस्थागत सुधारों के चलते भारतीय अर्थव्यवस्था में सकारात्मक माहौल को दर्शाता है। इस कथन का विश्लेषण कीजिये। (200 शब्द)

Recently credit rating agency Moody's has improved India's rating, which shows a positive environment in the Indian economy due to economic and institutional reforms made by the government over the past few years. Analyze this statement. **(200 words)**